भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3149

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

इंडिया एआई मिशन

3149. प्रो. सौगत राय :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है और यदि हां, तो इसमें निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू एआई आधारभूत मॉडल के प्रस्तावें का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें बड़ी भाषा-मॉडल और क्षेत्रविशिष्ट छोटी भाषा मॉडल को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव भारत-विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों के आधार पर उपयुक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **7 मार्च, 2024 को इंडियाएआई मिशन** को मंजूरी दे दी है, जो देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है।

इंडियाएआई मिशन में एआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख स्तंभ, जिनमें इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई शामिल हैं।

कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने, घरेलू एआई विशेषज्ञता को बढ़ावा देने, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देने, स्टार्टअप उपक्रमों का समर्थन करने, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई परियोजनाओं को बढ़ावा देने और नैतिक पद्धतियों पर बल देने के माध्यम से, मिशन का उद्देश्य भारत के एआई परिदृश्य में उत्तरदायी तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

इस दिशा में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एमईआईटीवाई ने इंडिया एआई मिशन को कार्यान्वित करने हेतु डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडियाएआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (आईबीडी) की स्थापना की है।

10,371.92 करोड़ रु.की धनराशि के कुल परिव्यय के साथ 'इंडियाएआई मिशन' का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के लिए है। इसके सात प्रमुख स्तंभों के बीच बजटीय परिव्यय का विस्तृत आबंटन इस प्रकार है:

घटक	**कुल व्यय**(₹ करोड़)
इंडियाएआई कंप्यूट कैपैसिटी	4563.36
इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी)	1971.37
इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म	199.55
इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल	689.05
इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स	882.94
इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग	1942.5
सुरक्षित और विश्वसनीय एआई	20.46
इंडियाएआई ओवरहेड्स और कंटेंजेन्सी @1%	102.69
कुल	10,371.92

इंडियाएआई ने दिनांक: 30 जनवरी, 2025 को एक **कॉल फॉर प्रपोजल** लॉन्च किया था, जिसमें स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों से भारतीय डेटासेट पर प्रशिक्षित अत्याधुनिक आधारभूत एआई मॉडल बनाने पर सहयोग करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी एआई मॉडल स्थापित करना है जो भारतीय संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों का सामना एवं अवसरों का लाभ प्राप्त कर करते हुए वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।
प्रथम माह में, इंडियाएआई मिशन को **15 फरवरी तक कुल 67 प्रस्ताव** प्राप्त हुए हैं, जिनका उद्देश्य भारत के आधारभूत मॉडल का निर्माण करना है, जिसमें स्थापित स्टार्टअप और शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की नई टीमों का योगदान शामिल है। 22 प्रस्ताव बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) पर केंद्रित हैं, जबकि शेष 45 डोमेन-विशिष्ट मॉडल (एसएलएम) पर केंद्रित हैं। अधिकांश एसएलएम स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हैं। फंडिंग सहायता के साथ-साथ, इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने वाली टीमों द्वारा कई प्रकार के जीपीयू का भी अनुरोध किया गया है।

*****